>

Title: Regarding construction of Loharinag Pala Dam Hydro-Electric Project on river Ganga in Uttarkashi, Uttarakhand by NTPC.

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर): मैडम, मैं इस सदन का ध्यान प्रोफेसर जी. डी. अग्रवाल की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं जो आईआईटी के प्रोफेसर थे और अभी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लोहारी नागपाला डैम न बने, उसके खिलाफ वह भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब पिछली बार वह भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो हमारे यहां से पावर मिनिस्ट्री ने एक आश्वासन दिया था कि हम एक कमेटी सेट-अप करेंगे और अगर वह हमें सही रिपोर्ट देती है, तो हम इस प्रोजेक्ट को ओ.के. करेंगे, तब तक हम इसको सस्पेंड करते हैं। इसके बाद वह अड़तीसवें दिन फास्ट से उठे। कमेटी भी सेट-अप हुयी और नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथारिटी बनी। उसके जितने भी एक्सपर्ट मेंबर्स हैं, सभी नौ मेंबर्स इस लोहारी नागपाला प्रोजेक्ट के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं और सारे के सारे इसके खिलाफ हैं। टेक्निकल कमेटी वहां यह पता करने के लिए भेजी गयी थी कि कितना काम हो चुका है और क्या वह डैमेज रीट्रिएबल है? उन्होंने कहा कि हां डैमेज हुआ है, पर वह रीट्रिएबल है। जितने इन्वायर्नमेंट नार्म्स हैं, शुरू से लेकर आखिर तक वहां उस डैम के ऊपर सारे एन्वायर्नमेंटल लॉज तकरीबन फ्लाउट किए गए हैं। जब तक हिमालयन नदियों के ऊपर हम लोग क्यूमेलेटिव इंपैक्ट एसेसमेंट नहीं करा लेते, क्योंकि हर एक एन्वायर्नमेंट की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, अगर हम अंधाधुंध उसके ऊपर डैम बनाते जाएंगे, देश को पावर की जरूरत है, यह मैं भी समझती हूं, पर क्या देश को पानी की जरूरत नहीं है? वाटर सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज करके पावर सिक्योरिटी लाने में ज्यादा विवेक मेरे हिसाब से समझ में नहीं आता कि हम लोग इसे काम में ले रहे हैं या नहीं। एन्वायर्नमेंट मिनिस्टर ने 16 जुलाई को प्रोटेस्टर्स के सामने यह कहा था कि reasons are purely fiscal, not environmental. फिस्कल में उन्होंने कहा था कि चालीस पर्सेंट काम इस डैम का हो चुका है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसका बाकी काम कराया जाए। आरटीआई की एक इंक्वायरी की जवाब में आया कि इसमें पांच सौ करोड़ रूपए खर्च हुए हैं। 29 सौ करोड़ रूपए के प्रोजेक्ट के अंदर पांच सौ करोड़ रूपए का मतलब हुआ कि 17 प्रतिशत पैसा खर्च हुआ। उन्होंने कहा चालीस पर्सेंट काम खत्म हो गया। 13.85 किलोमीटर लंबी सुंग बननी थी, जिसमें से मात्र 2.56 किलोमीटर लंबी सुंग बनी है, जो लगभग 17-18 पर्सेंट हुआ।

पहली बात यह है कि चालीस पर्सेंट काम वहां नहीं हुआ। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं इस डैम के खिलाफ हूं, but there are people in the Ministry who think otherwise. मेरा कहना है कि जो हमारी नेशनल रिवर है, इकलौती रिवर जिसका सोर्स हमारे कंट्रोल में है, दूसरी रिवर्स के साथ चाइना क्या कर रहा है, उसके लिए हम ज्यादा चिंतित हैं, पर एकमात्र जो सोर्स हमारे कंट्रोल में है और हम अपनी नदी के साथ क्या करना चाह रहे हैं? मेरा सरकार से निवेदन है कि प्रो. जी.डी. अग्रवाल की स्थिति आज बिगड़ने लगी है क्योंकि 20 जुलाई से इसी चीज को लेकर वह भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वह साइंटिस्ट हैं, भावनाओं में बहकर यह काम नहीं कर रहे हैं, प्योरली साइंटिफिक बेसिस के ऊपर ऐसा कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि रीजन फाइनैंशियल हैं। फाइनैंशियल रीजन के लिए जो धार्मिक नेता वहां इस मुहिम में जुटे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको पैसा रीअंबर्स करेंगे, सरकार ने उनके आफर को ठुकरा दिया। मुझे यह समझ में नहीं आता कि जब कोई प्रोजेक्ट एन्वायर्नमेंटली, इकानामिकली, कल्चरली, सोशियली वाइबल नहीं है, तो सरकार उसको ओ.के. करके कैसे कह सकती है कि हम इसको आगे बनाना चाहते हैं? मेरा यह निवेदन है कि गंगा की जितनी भी हिमालयन रिवर्स हैं, उन सभी के ऊपर जब क्यूमेलेटिव इंपैक्ट एसेसमेंट नहीं हो जाए, तब तक के लिए सारे प्रोजेक्ट्स को सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि पावर से पहले हमें पानी की सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। जो पानी गंगा में आता है, वह राजस्थान में पाइप लाइन के थ्रू मेरी कांस्टीच्युंसी में भी पानी पहुंच रहा हे, जो कि पीने के काम आता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि जी.डी. अग्रवाल जी को भूख हड़ताल से उठाया जाए और तब तक इनको सस्पेंड किया जाए जब तक कि इन सभी निदियों पर क्यूमेलेटिव एसेसमेंट नहीं होता।